

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ,

2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर 112212

कमांकएफ.11(3)मो./मनरे. कन्व. बजट-घोषण 16/आईसीडीएस/2016-17/

जयपुर दिनांक:

प्रेषक :-

प्रेषिति :-

24.8.16

उप शासन सचिव,  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
राजस्थान, जयपुर

निदेशक,  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत कन्वर्जेन्स के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु किशत की राशि जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित करने की प्रशासनिक स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के अनुसार किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण किये जाने हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत कन्वर्जेन्स के तहत जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल 2000 आंगनबाड़ी केन्द्र में से प्रथम चरण के लिए 1000 आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं द्वारा राशि रु. 2.00 लाख की इकाई लागत के आधार पर कुल राशि रु. 2000.00 लाख (अक्षरे रूपये दो हजार लाख मात्र) उनके निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

जिला परिषदों को स्वीकृत राशि का उपयोग उपरोक्तानुसार जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण मनरेगा कन्वर्जेन्स के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.02.2016 जारी गाईडलाईन के तहत भवन निर्माण किया जायेगा (प्रति संलग्नानुसार)। यह स्वीकृति भारत सरकार की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 31.05.2016 के क्रम में जारी की जा रही है। जिसके द्वारा प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु समेकित बाल विकास सेवाएँ की राशि 2.00 लाख रूपये निर्धारित की गई है, केन्द्र व राज्य की हिस्सेदारी 60:40 की है। इन भवन निर्माण कार्यों हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3), शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक एफ.40(79)ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेन्स-आ.बा.भवन/2014-15 दिनांक 10.11.2015 को जारी परिपत्र के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग की योजना के साथ कन्वर्जेन्स (अभिसरण) के माध्यम से आंगनबाड़ी भवन निर्माण दिशा निर्देशानुसार भवन निर्माण कराया जावे।
2. आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु एक सुझावात्मक ड्राफ्ट टाइप डिजाइन संलग्न है। जिसमें स्थानीय आवश्यकता तथा अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है। निर्माण में विभागीय लाभार्थियों (बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं) की सुविधा व आवश्यकता को विशेष ध्यान में रखें।
3. आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार इकाई लागत के अनुरूप करवाये जाएंगे।
4. आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी होने से 6 माह में निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा।
5. आंगनबाड़ी भवन निर्माण उन्हीं स्थानों पर करवाया जा सकेगा, जिनकी सूची उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ प्रमाणित कर जिला परिषदों को उपलब्ध करवायेगे। प्राप्त हुए निःशुल्क भूमि के पट्टे पर निर्माण से पूर्व आवंटित भूमि के स्थल का संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी से मौका मुआयना कराने तथा विभागीय आवश्यकता व शर्तों के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे तथा जिस स्थान का प्रमाण पत्र दिया गया है, उसी स्थान पर निर्माण कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। यहाँ यहाँ भी सुनिश्चित किया जाये जिस केन्द्र के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हो रहा है वह किराये के भवन में संचालित होना चाहिए।

6. इस प्रयोजनार्थ उपयोग में ली गई राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ को भिजवाये जाने होंगे। भारत सरकार द्वारा द्वितीय किशत की राशी प्रथम किशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर जारी की जावेगी।
7. इस राशि के व्यय के पश्चात जिला परिषद राशि के अंकेक्षित लेखे एवं जिस कार्य हेतु राशि दी गई है, उसी कार्य में उपयोग लिये जाने का प्रमाण-पत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विभाग को भिजवायें। जिला परिषद नियमित रूप से योजना का प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में प्रतिमाह भिजवायेगे। साथ ही जो भी सूचना राज्य सरकार द्वारा चाही जावे, उपलब्ध करवायेगे।
8. जिला परिषद द्वारा इस योजना के लिए पृथक-पृथक लेखे रखे जावेगे। जिसकी महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा जांच की जा सकेगी। मासिक व्यय विवरण प्रतिमाह निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
9. भवन का कब्जा संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मय खिडकी, दरवाजे, रंग, पुताई, फर्श आदि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही प्राप्त किये जा सकेगे।
10. आंगनबाडी भवन निर्माण की गुणवत्ता तथा नियत अवधि तक कार्यशीलता का उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा। सामान्यतः भवन का जीवनकाल (Self Life) सौ वर्ष माना गया है। इससे पहले अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त भवन के पूर्णतः अनुपयोगी होने तथा क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में निर्माणकर्ता एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी व भवन की मरम्मत का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का होगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई डी संख्या 161600940 दिनांक 04.08.2016 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। इस राशि का उपयोग हेतु RTPPA की पालना किया जाना सुनिश्चित करावे।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



उप शासन सचिव

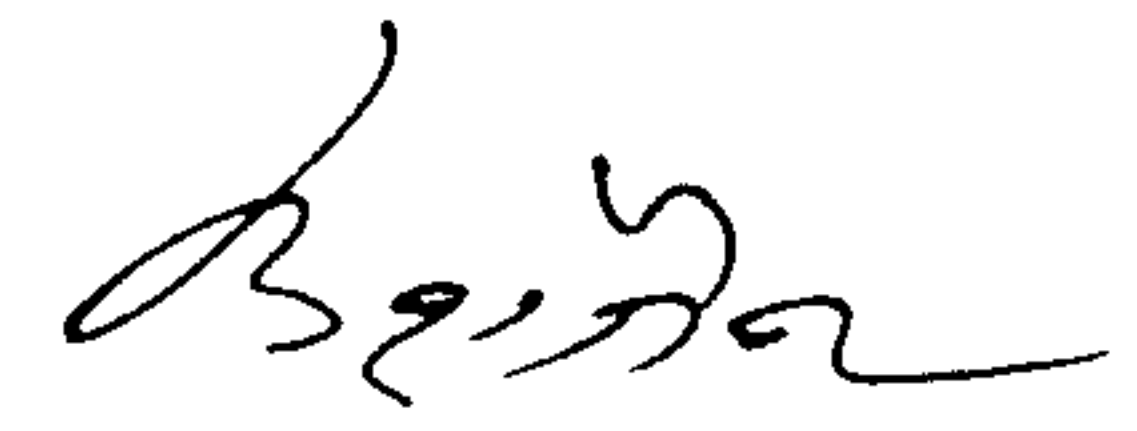
महिला एवं बाल विकास विभाग,

राजस्थान जयपुर

कमांकएफ.11(3)मो./मनरे. कन्व. बजट-घोषण 16/आईसीडीएस/2016-17/  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर दिनांक: 24.8.18

1. विशिष्ट सहायक, माननीया राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), लेखा परीक्षा-प्रथम, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, मुख्यालय, राज. जयपुर।
7. निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
8. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सम्बन्धित जिला कोषालय को परिशिष्ट 1 में विवरणानुसार राशि रूपये 2000.00 लाख (अक्षरे राशि रु. दो हजार लाख मात्र) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करवाये जाने की स्वीकृति शीघ्र प्रसारित कर सूचित करने का श्रम करावे।
9. समस्त जिला कलक्टर।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, राज. जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
12. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान।
13. ACP को विभागीय वेब साईट पर अपलोड हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।
15. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।



उप शासन सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग,



प्रत्येक जिले में मदवार आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति

परिशिष्ट-1

(राशि लाखों में)

क्र.स.	जिले का नाम	महानरेगा कवर्जेंट्स के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की किरत के रूप में मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषदों(शा.वि.प्र.) के पीडी खातों में हस्तान्तरित की जाने वाली राशि बजट मदवार																		
		सामान्य मद 4236-02-800-09-00-17 वृहद निर्माण कार्य					एससीएसपी मद 4236-02-789-01-00-17 वृहद निर्माण कार्य					टीएसपी मद 4236-02-796-01-00-17 वृहद निर्माण कार्य					स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या		कुल राशि	
		स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	केन्द्र मद	राज्य मद	योग	स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	केन्द्र मद	राज्य मद	योग	स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	केन्द्र मद	राज्य मद	योग	स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	केन्द्र मद	राज्य मद	योग	राज्य मद	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	अजमेर	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
2	अलवर	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
3	बांसवाड़ा	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
4	बारा	29	34.80	23.20	58.00	6	7.20	4.80	12.00	0	0.00	0.00	0.00	35	42.00	28.00	70.00			
5	बाड़मेर	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
6	भरतपुर	22	26.40	17.60	44.00	6	7.20	4.80	12.00	0	0.00	0.00	0.00	28	33.60	22.40	56.00			
7	भीलवाड़ा	78	93.60	62.40	156.00	17	20.40	13.60	34.00	0	0.00	0.00	0.00	95	114.00	76.00	190.00			
8	बीकानेर	24	28.80	19.20	48.00	6	7.20	4.80	12.00	0	0.00	0.00	0.00	30	36.00	24.00	60.00			
9	बूंदी	74	88.80	59.20	148.00	16	19.20	12.80	32.00	0	0.00	0.00	0.00	90	108.00	72.00	180.00			
10	चित्तौड़गढ़	57	68.40	45.60	114.00	13	15.60	10.40	26.00	0	0.00	0.00	0.00	70	84.00	56.00	140.00			
11	चुरू	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
12	दौसा	24	28.80	19.20	48.00	6	7.20	4.80	12.00	0	0.00	0.00	0.00	30	36.00	24.00	60.00			
13	धौलपुर	11	13.20	8.80	22.00	3	3.60	2.40	6.00	0	0.00	0.00	0.00	14	16.80	11.20	28.00			
14	झुंझुनुर	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	50	60.00	40.00	100.00	50	60.00	40.00	100.00			
15	श्रीगंगानगर	41	49.20	32.80	82.00	9	10.80	7.20	18.00	0	0.00	0.00	0.00	50	60.00	40.00	100.00			
16	हनुमानगढ़	41	49.20	32.80	82.00	9	10.80	7.20	18.00	0	0.00	0.00	0.00	50	60.00	40.00	100.00			
17	जयपुर	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
18	जैसलमेर	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
19	जालौर	145	174.00	116.00	290.00	55	66.00	44.00	110.00	0	0.00	0.00	0.00	200	240.00	160.00	400.00			
20	झालावाड़	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
21	झुन्झुनुर	16	19.20	12.80	32.00	4	4.80	3.20	8.00	0	0.00	0.00	0.00	20	24.00	16.00	40.00			
22	जोधपुर	17	20.40	13.60	34.00	3	3.60	2.40	6.00	0	0.00	0.00	0.00	20	24.00	16.00	40.00			
23	करौली	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
24	कोटा	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
25	नागौर	17	20.40	13.60	34.00	3	3.60	2.40	6.00	0	0.00	0.00	0.00	20	24.00	16.00	40.00			
26	पाली	29	34.80	23.20	58.00	6	7.20	4.80	12.00	0	0.00	0.00	0.00	35	42.00	28.00	70.00			
27	प्रतापगढ़	13	15.60	10.40	26.00	12	14.40	9.60	24.00	43	51.60	34.40	86.00	68	81.60	54.40	136.00			
28	राजसमन्द	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
29	सवाईमाधोपुर	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
30	सीकर	32	38.40	25.60	64.00	8	9.60	6.40	16.00	0	0.00	0.00	0.00	40	48.00	32.00	80.00			
31	सिरोही	7	8.40	5.60	14.00	0	0.00	0.00	0.00	8	9.60	6.40	16.00	15	18.00	12.00	30.00			
32	टोंक	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
33	उदयपुर	13	15.60	10.40	26.00	0	0.00	0.00	0.00	27	32.40	21.60	54.00	40	48.00	32.00	80.00			
	कुल योग	690	828.00	552.00	1380.00	182	218.40	145.60	364.00	128	153.60	102.40	256.00	1000	1200.00	800.00	2000.00			

*(Handwritten signature)*

19

F.No.CD-14/102/2015-CD II  
Government of India  
Ministry of Women & Child Development

Shastri Bhawan, New Delhi  
Dated: 31<sup>st</sup> May 2016

To

Chief Controller of Accounts,  
Pay & Accounts Office,  
Ministry of Women & Child Development,  
Shastri Bhawan, New Delhi.

**Subject:** Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme - Release of grants-in-aid to State Governments during the year 2016-17 for construction of AWC buildings under MGNREGA in convergence with ICDS in first phase.

Sir,

I am directed to convey the sanction of the President to the payment of **Rs.501,85,20,000/- (Rupees Five Hundred One Crore Eighty Five Lakh & Twenty Thousand only)** to the State Governments mentioned in column 2 as per individual amount of first instalment mentioned in column 5 against each as grants-in-aid approved for construction of AWC buildings in convergence with MGNREGA in first phase during the year 2016-17:

Rs. in Lakhs				
S. No.	States	No. of AWC buildings proposed to be constructed in convergence with MGNREGA during the year 2016-17	No. of AWC buildings to be constructed in first phase	Amount released in 1 <sup>st</sup> instalment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Andhra Pradesh	4420	2210	2652.00
2	Bihar	12000	6000	7200.00
3	Chhattisgarh	2000	1000	1200.00
4	Gujarat	500	250	300.00
5	Haryana	750	375	450.00
6	Jharkhand	5000	2500	3000.00
7	Karnataka	3000	1500	1800.00
8	Kerala	1000	500	600.00
9	Madhya Pradesh	7000	3500	4200.00
10	Maharashtra	2000	1000	1200.00
11	Odisha	8370	4185	5022.00
12	Punjab	1000	500	600.00
13	Rajasthan	2000	1000	1200.00
14	Tamil Nadu	5000	2500	3000.00
15	Telangana	2000	1000	1200.00
16	Uttar Pradesh	20602	10301	12361.20
17	West Bengal	7000	3500	4200.00
	<b>Total</b>	<b>83642</b>	<b>41821</b>	<b>50185.20</b>

Contd...2

*[Signature]*  
31.05.2016

50  
800  
2000



2. The works for construction of AWC buildings are to be taken up as per approved District Plans. The construction of AWC buildings are to be undertaken through convergence of resources among MoWCD, MoRD & MoPR in current year and included in District Plans of these districts. The funding pattern for construction of AWC buildings in convergence with MGNREGA will be as under:

- (i) Funds provided under MNREGA by MoRD upto Rs.5.00 Lakh; ✓
- (ii) Funds to be met from ICDS Rs.2.00 Lakh ✓  
(60:40 between the Centre and States); and
- (iii) Cost over and above Rs.7.00 lakh, if any, will be borne by the concerned State Governments

3. This grants-in-aid is towards the non-recurring and recurring expenditure for the ICDS Programme. The payment is provisional and is subject to final adjustment in the light of the audited figures of actual expenditure for the year as a whole *vide* Ministry of Finance's letter No.2(19)-P.II/60, dated 09.10.1964, as amended from time to time, addressed to all State Governments, etc.

4. The grants-in-aid is subject to the condition that when the Scheme is closed or abandoned, the receipt from the disposal of assets, built out of the whole or a portion of the grant now sanctioned, will be shared between the Governments in proportion with their respective shares in the capital cost to assets.

5. The expenditure is debitable to '3601'-Grants-in-aid to State Governments (Major Head); 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head); 02.358-Social Welfare-Child Welfare (Minor Head); 09-UMBRELLA ICDS; 01-Core ICDS Integrated Child Development Services; 09.01.35-Grants for Creation of Capital Assets (Plan) under Demand No.97 of the Ministry of Women & Child Development for the year 2016-17.

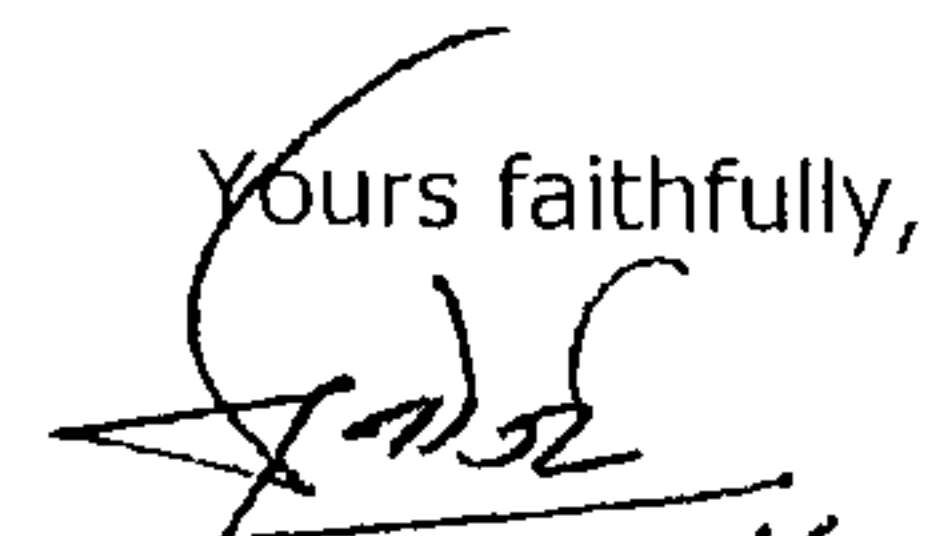
6. The amount of grants-in-aid is finally adjustable in the books of the Principal Pay & Accounts Office, Ministry of Women & Child Development, Shastri Bhawan, New Delhi. The payment of these States would be arranged through the Reserve Bank of India, Nagpur. The State Accountant General will send intimation regarding receipt of grants-in-aid to the Principal Pay & Accounts Office, Ministry of Women & Child Development, Shastri Bhawan, New Delhi.

7. The State Governments may ensure that the funds released are utilized within the current financial year or within 6 months from the date of release of funds for construction of AWCs and separate Utilization Certificate/SoE and physical progress report of the construction of AWC buildings may be submitted.

8. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme approved by the Ministry of Finance.

9. This sanction issues with the concurrence of IFD *vide* Dy. No. F. No.CD-II 14/102/2015-CD.II, dated 26.05.2016.

Yours faithfully,

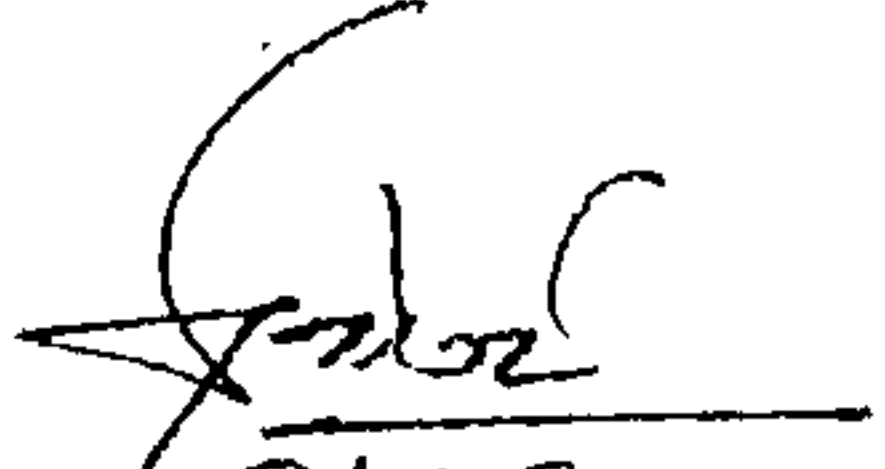
  
31.05.2016  
(MANOJ KUMAR)

Under Secretary to the Government of India

(मनोज कुमार/MANOJ KUMAR)  
अवर सचिव/Under Secretary  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
Ministry of Women & Child Dev.  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi

**Copy forwarded to:**

1. Secretary (dealing with ICDS), State Governments as indicated in para 1.
2. Secretary (Department of Health), State Governments as indicated in para 1.
3. Secretary (Department of Finance), State Governments as indicated in para 1.
4. Secretary (Department of Planning), State Governments as indicated in para 1.
5. Director (dealing with ICDS), State Governments as indicated in para 1.
6. Accountant Generals, State Governments as indicated in para 1.
7. Director of Audit, Central Revenues, AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi.
8. Ministry of Finance (Department of Expenditure) [Plan Finance Division], North Block, New Delhi.
- 9-12. PS to Minister, WCD/PPS to Secretary, WCD/PS to JS (RK)/Director (KBS)/US (Budget).
13. Director, NIC for uploading on Ministry's website.

  
31.05.2016  
(MANOJ KUMAR)

Under Secretary to the Government of India

(मनोज कुमार/MANOJ KUMAR)  
अवर सचिव/Under Secretary  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
Ministry of Women & Child Dev.  
भारत सरकार, Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi

46

No. J-11016/11/2012-MGNREGA-IV  
Government of India  
Ministry of Rural Development  
Department of Rural Development  
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhawan, New Delhi  
Dated: 17.2.2016

To : The Spl. SGs/Pri. Secretaries/Secretaries of Rural Development (In-charge - MGNREGA).

Sub : Guidelines for construction of Anganwadi Centres under MGNREGA In convergence with ICDS scheme of Ministry of Women and Child Development.

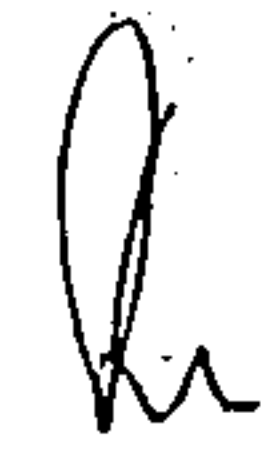
Sir/Madam,

As per Para 4(1) IV (v) of Schedule - 1, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), construction of buildings for Anganwadi centres is permitted.

In view of the above, the guidelines for construction of Anganwadi Centres under MGNREGA In convergence with ICDS scheme of MoWCD and other suitable schemes jointly signed by the Secretary, Department of Rural Development, Secretary, Ministry of Women and Child Development and Secretary, Ministry of Panchayati Raj is enclosed herewith for necessary action at your end.

It is requested to share these guidelines with the concerned functionaries for taking up the construction of Anganwadi Centres in the Identified/to be Identified locations.

Yours faithfully,

  
(Aparajita Sarangi) 17/2/16  
Joint Secretary (MGNREGA)

Encl: As above.

Copy to : PPS to Secretary, MoRD, Ministry of Rural Development/Ministry of Women and Child Development/Ministry of Panchayati Raj for Information.



27  
GUIDELINES FOR CONSTRUCTION OF ANGANWADI CENTRES UNDER  
MGNREGS IN CONVERGENCE WITH ICDS SCHEME OF THE MINISTRY OF  
WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

1. CONTEXT:

ICDS

1.1 The Government is committed to repositioning the Anganwadi Centre (AWC) as a "vibrant ECD centre" to become the first village outpost for health, nutrition and early learning. Towards this end, several steps have been taken for improvement and strengthening of ICDS scheme covering programmatic, management and institutional areas.

1.2 Whereas intensive efforts are being made for improving the service delivery at the Anganwadi centres, an estimated 4 lakh AWCs have no building to locate their activities. There is therefore an urgent need to take up construction of buildings for these AWCs. The MWCD has issued guidelines stating that AWCs should be child friendly with all relevant infrastructures and the space should be at least 600 sq. ft. Although there is a scheme for construction of AWCs at a unit cost of @ Rs. 4.5 lakh per unit under ICDS, it was felt that this can best be done through convergence of schemes like MGNREGA.

MGNREGA

1.3 The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) 2005 aims to provide unskilled manual work to any rural household on demand and employing them on construction of productive assets. Construction of Anganwadi Center is a permissible work as per para 4(1) iv of Schedule I of the MGNREGA 2005. In order to ensure that the focus of these works would remain on creation of wage employment, there is a statutory limit on the cost of material component including the wages of the skilled and semi skilled workers at forty percent of the total project cost at the level of each Gram Panchayat for all GP executed works and at the District level for works taken up by other agencies.

1.4 These joint guidelines aim at building a systematic convergence of ICDS, MGNREGS and resources of Panchayati Raj Institutions, especially 14<sup>th</sup> Finance Commission grant so that every AWC in the Blocks covered under MGNREGA is provided with own building. Each year, there shall be at least 1 lakh AWCs constructed under this convergence for the next 4 years, resulting in construction of 4 lakh AWCs by 2019.

1.5 States/UTs would identify the location for 1 lakh AWCs in the Blocks where there is acute shortage of AWC building. The identification of exact location will be done by the Gram Panchayats which shall form part of District Plan sent through the States to MWCD.



1.6 Criteria for selection/identification of AWCs: The following criteria shall be followed:

- a. The selection of exact location for construction of AWC buildings will be done by the Gram Panchayats at the village level. It should be sent to the CDPO, ICDS for consolidating all such proposals for further processing.
- b. The proposals received from the Gram Panchayats shall be consolidated at the Block level by the CDPO and sent to the District Programme Officer at the District level which shall form part of the District Plan. The criteria of selection shall be mentioned in the District Plan. District Plan for construction of AWC buildings shall also be drawn.
- c. All such proposals received at the District Plan shall be consolidated at the State level and the State, after considering these proposals shall forward the recommended proposals to the MWCD for consideration.
- d. A copy of District Plan approved shall be sent to State Department of WCD.

1.7 Phasing of construction of AWC buildings:

The construction of AWC buildings in convergence with MGNREGA will be executed in phases in the following manner:

- a. In 200 High Burden Districts in the first year;
- b. In second year, another 200 districts covering the North Eastern and Himalayan States and those States not covered in the first year.
- c. 50% of remaining districts in the third year.
- d. Remaining districts in the fourth year.

2) OBJECTIVES:

The following are the objectives of this convergence:

- (a) To ensure that every AWC in the Blocks covered under MGNREGA is provided with own building.
- (b) To serve the objectives of pre-school, nutrition centre, semi-formal public health unit, community centre located in the heart of settlements.
- (c) To support generation of human and social capital at the micro level.
- (d) To create durable assets in rural areas and improve the infrastructure at village level.
- (e) To provide creche facility to MGNREGA workers.
- (f) To enhance community participation.
- (g) To strengthen the role of Gram Panchayats in implementation of ICDS.

3) ACTIVITIES THAT CAN BE UNDERTAKEN UNDER MGNREGA IN ACCORDANCE WITH THESE GUIDELINES:

49  
Construction of Anganwadi Centre buildings (AWCs) as per instructions/guidelines of "Integrated Child Development Services Scheme (ICDS)" administered by Ministry of Women & Child Development (MWCD). Assistance from MGNREGA for AWCs will however, be limited to provisions in Para 7 below.

4. DESIGNS/ SPECIFICATIONS:

4.1. The total land area of the site for construction of AWC building should be 1500-2000 sq. ft. which should cover at least 600 sq.ft. of built up area, boundary wall, kitchen garden, play area, etc. The AWC building should be child friendly with all relevant infrastructure, separate sitting room for children/women, separate kitchen, store for storing food items and child friendly toilets and space for playing of children (indoor and outdoor activities). It should be equipped with safe drinking water. The designs/specifications should adhere to these instruction/guidelines and any further instructions which may be issued by Ministry of Women & Child Development, Government of India, from time to time.

4.2. Local design variation depending on the geo climatic conditions and construction material will also follow instructions/ guidelines mentioned above.

4.3. If any Gram Panchayat chooses to make an AWC of a bigger dimension, same will also be allowed. However, payment from MGNREGA will be restricted to provisions given at Para 7 of these guidelines.

4.4 The Building so constructed will be the property of the Gram Panchayat, which will be responsible for its proper maintenance.

5. NON NEGOTIABLES IN WORK EXECUTION:

- a) There shall be no contractors in execution. The work shall be undertaken by the implementing agency, working with the job card holders.
  - b) Only Job Card holders will be employed for the unskilled part of work.
  - c) Muster Rolls will be maintained on the worksite, with copies in the Gram Panchayat. All data will also be in public domain and will be entered on [mrega.nic.in](http://mrega.nic.in)
  - d) Wage payments will be done through banks/post office accounts only unless exempted by Ministry of Rural Development.
  - e) Only eco-friendly building technologies that reduce the use of steel and cement, while constructing pucca buildings shall be used.
  - f) Transparency and pro-active disclosures related to procurement of material/use of funds.
- 4



g) Social Audit.

## 6 CONFORMITY TO MAHATMA GANDHI NREGA PROCESSES IN PLANNING AND EXECUTION :

### 6.1 PLANNING :

- a. Functionaries of ICDS will participate in the planning exercise being undertaken to identify works with the community participation.
- b. The planning process will be Gram Panchayat (GP) based. GP wise and year wise list of AWCs proposed for construction under ICDS phased programme will be put up in the Gram Sabha for approval and inclusion in shelf of projects. The proposal will be sent to CDPO, ICDS for consolidation at the block level.
- c. All AWCs proposed for construction under MGNREGS shall be part of the District plan, approved by the Gram Sabha and the Gram Panchayat and shall also be a part of the annual shelf of projects.
- d. The proposals received from the Gram Panchayats shall be consolidated at the Block level by the CDPO, ICDS and sent to the District Programme Officer at the District level which shall form part of the District Plan. The criteria of selection shall be mentioned in the District Plan. District Plan for construction of AWC buildings shall also be drawn.
- e. All such proposals received at the District level shall be consolidated at the State level and the State after considering these proposals shall forward the recommended proposals to the MWCD for consideration.
- f. MWCD would facilitate that wherever Panchayats have their own land, they would make it available for the purpose of construction of AWCs preferably near primary schools in the respective villages.

### 6.2 ESTIMATES :

- (a) An electronic estimate module shall be made available under NREGA Soft, formulated with standard estimate, design and specifications.
- (b) After approval of the Gram Sabha and the Gram Panchayat, the concerned Technical Assistant/ Junior Engineer of the Panchayat/Line department will prepare e-estimate for the AWC works using the estimate module following the prevailing SOR for MGNREGA works in the area.
- (c) The Technical Sanction will be issued by the concerned authority electronically as per norms/ power delegated for MGNREGA works.
- (d) After the TS issued, AS/FS will be issued by the concerned as per norms/ power delegated for MGNREGA works.

5  
1



51

## 6.2 EXECUTION

- a. The Project Implementing Agency (PIA) for the construction of the AWC would be decided by the State Government.

However, a list of agencies for execution of construction work shall be short listed and notified by the States. The GPs shall select one of these notified agencies for executing construction of AWC building works. Some of the suggested agencies are State PWD, DRDA, State Housing Boards, Public Sector Undertakings of the Central and State Governments, etc.

- b. On receipt of a request from the GP, the PO will issue muster rolls.
- c. Every AWC will be treated as an independent work with work I.D. No. and muster roll issued accordingly.
- d. A mate may be deployed for every AWC proposed to be taken up in a Gram Panchayat at one time. The designated mate will be responsible for the following :
- i. Maintain muster for all AWCs in the GP/Village/locality assigned to him.
  - ii. Record attendance for skilled and unskilled labour.
  - iii. Ensure that the construction is as per the design/ drawing specified in the TS and will certify to that effect.
  - iv. The mate will sign the muster roll for attendance and hand it over to the Junior Engineer/ Technical Assistant for further processing.
- e. The PIA would be responsible for supply of the material in advance and as per requirement at the site, so that work can be taken up continuously, without a break.
- f. The building material required for the building can be produced on the site as a part of the estimate. It shall be ensured that building material shall be eco-friendly minimizing the use of cement and steel.
- g. The TAJE shall record the MB for all such units. The measurement of the work will be made weekly by the concerned TAJE as per the norms under MAHATMA GANDHI NREGA. The entries of measurement with assessment of work will be entered in measurement book as well in the muster roll.
- h. The completion period of each AWC building shall not be more than 11 months from the date of commencement of the work.

## 7. MODE OF EXPENDITURE:

7.1 The construction of AWC building will be taken up under MGNREGS using appropriate building technologies, through muster rolls as per MAHATMA GANDHI NREGA process:

6

52

7.2 Under MGNREGA expenditure up to Rs. 5 lakhs will be allowed for construction of an AWC building.

Beyond this, the expenditure will be borne from the ICDS scheme of the Ministry of Women and Child Development, including finishing of the building consisting of flooring, painting, plumbing, electrification and wood work etc., as a separate work. For this purpose, concerned authorities at District/Block level shall release the funds, to the PIA concerned.

The ICDS funds for construction of AWC buildings to the extent of Rs 2 lakh per unit will be released by the Central Government in two instalments in the prescribed cost sharing ratio to the State. The State Government, in turn, will release such funds to the Implementing Agency at the District/Block level through PFMS/IFMS. Such Implementing Agency shall further release the money to the executing agency. Since the ICDS funds are to be utilised for finishing of the building consisting of flooring, painting, plumbing, electrification and wood work etc., these funds shall be released by the Implementing Agency at an appropriate time during the course of construction.

If the cost estimate of the AWC building is more than Rs. 7 lakh, the additional cost over and above Rs. 7 lakh shall be met by the State Government from its own resources.

Apart from this, funds from sources like State Finance Commission, Scheduled Castes Sub Plan (SCSP), Tribal Sub Plan (TSP), 14<sup>th</sup> Finance Commission (for water supply & sanitation) or any other suitable scheme may be used for the construction of AWC building.

7.3 Ministry of Panchayat Raj would facilitate to provide drinking water facilities and sanitation structures at the AWCs wherever the gaps regarding these facilities exist.

#### 8. USE OF ECO-FRIENDLY DESIGNS AND MATERIAL:

The AWC buildings taken up under this project shall be model buildings using eco-friendly materials that conform to the following:

- a. The appropriate technologies for the AWC buildings shall be in accordance with the local building traditions, while keeping in view the durability.
- b. The use of cement, sand and steel in construction shall be substantially reduced through:
  - i. Use of local material, local practices for stub foundations or arch foundations or under reamed piles, with suitable design and specifications to address the needs of the relevant seismic zone.
  - ii. Avoiding the use of concrete columns and beams wherever the span of construction is less than 6 meters in a single-storied structure (or 4 meters in case of more than 2 floors) by using alternate technologies, wherever the soils permit.



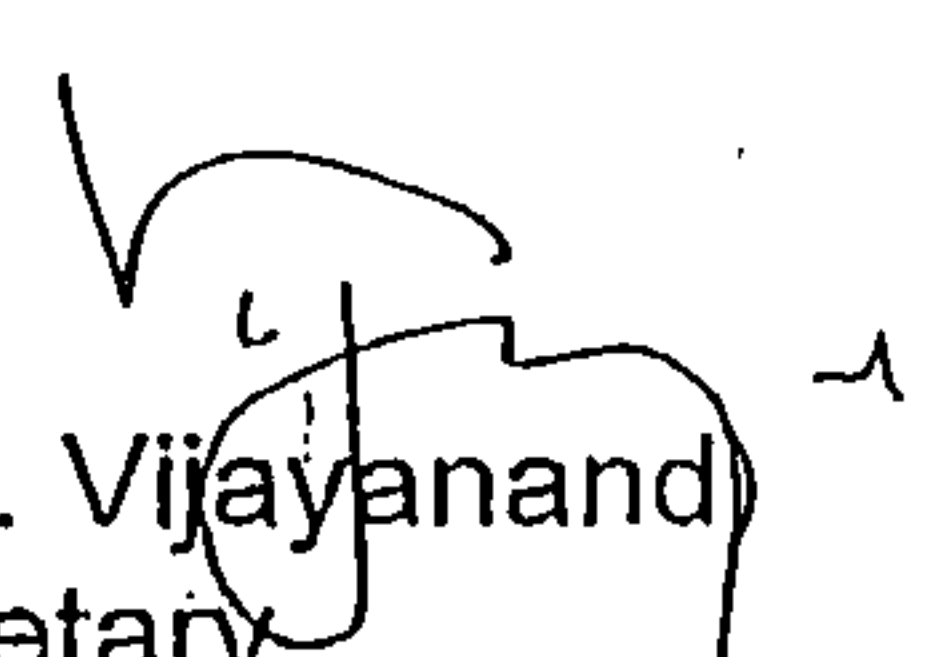
53


- iii. Use of rat-trap bond in all walling work using bricks or blocks 250 mm X 120 mm X 85 mm or equivalent sizes as locally adopted.
  - iv. Avoiding cement plastering to the extent possible on both sides of the wall.
  - v. Use of filler slabs using tiles or local material to reduce the concrete.
  - vi. Avoiding RCC sunshades (chajjas) and replacing with stone/ferro-cement or suitable materials locally available.
  - vii. Replace windows with honeycomb structures wherever local climate permits.
  - viii. Use of local material like stone etc. for door and window frame and minimize the use of wood.
  - ix. Use of local material for flooring like local stone and bricks etc.
  - x. Use of appropriate mud-based technology.
- c. Suitable building material shall be selected for each building (Indicative list below) and produced at the site of construction (using the MGNREGA workers) such that the labour component in the building shall be maximized:
- i. Mud blocks
  - ii. Stone and renewable wood (e.g. casuarina)
  - iii. Compressed and stabilized earth blocks (after due treatment and curing)
  - iv. Bamboo material
  - v. Fa-G bricks using the fly ash
  - vi. Filler blocks
  - vii. Micro concrete roofing
  - viii. Funicular roofing, etc.

**9. MONITORING AND REPORT:**

Progress of construction of AWCs under MAHATMA GANDHI NREGS shall be the responsibility of the District Programme Coordinator (DPC) and the agency implementing ICDS Scheme as mentioned in the respective guidelines. The construction of all AWCs under MAHATMA GANDHI NREGS will be subject to social audit as per MAHATMA GANDHI NREGS and ICDS regulation/guidelines.

  
(J.K. Mohapatra)  
Secretary  
Ministry of Rural  
Development

  
(S.M. Vijayanand)  
Secretary  
Ministry of Panchayati Raj

  
(V. Somasundaran)  
Secretary  
Ministry of Women & Child  
Development



Activity mapping for construction of AWC buildings in convergence with MGNREGA

Activity	Agency/ details
Eligible blocks	All blocks (IPPE and non-IPPE) covered under MGNREGA having acute shortage of AWC buildings.
Total AWC Buildings to be constructed.	4 lakh by 2019 @ 1 lakh AWC buildings per year.
Planning for construction	State Government. Planning to be done at GP level and shall form part of District level approved by Gram Sabha and GP as per para 6.1 of the guidelines.
Provision of land	State Government, Panchayats.
Identification of location.	Gram Panchayat/ at the village level. The proposal shall form part of the District Plan.
Design specifications.	MWCD - minimum area of 600 sq.ft, child friendly building with all relevant infrastructures, separate sitting room, kitchen, store, child friendly toilets, playing space.
Construction of AWC building.	Panchayati Raj institutions.
Provision of Drinking Water & Sanitation	Gram Panchayas - by utilising the funds provided under the 14 <sup>th</sup> Finance Commission to the States/UTs.
Availability of funds under MGNREGA	Upto Rs. 5 lakh for construction of AWC building.
Availability of funds by Ministry of WCD	Upto Rs. 2 lakh for finishing which consists of flooring, painting, plumbing, electrification and wood work, etc at cost sharing ratio of 60:40 between Centre and States (90:10 for NER and Himalayan States).
Material : wage component cost ratio under MGNREGA	Cost of material component including wages of skilled and semi-skilled workers at 40% of total project cost at the level of each GP for all GP executed works and at District level for works taken up by other agencies for MGNRES components.
Ownership of building	Gram Panchayat.
Monitoring	District Programme Coordinator and the agency implementing the ICDS scheme.
Maintenance	By Gram Panchayats using their own resources.